मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- मन्त्री पद को तरसते विधायक बेचारे
- मई दिवस : दुनिया के मज़दूरों एक हो! — 3
- पूंजीपतियों मालिकों, ठेकेदारों के राज में मज़दूरों की बढ़ती दुर्दशा — 5
- अपनी विफलताओं को अन्धविश्वास से ढकते हैं नेतागण — 6
- खेती उजाडने पर अमादा एन जी टी
- राजमार्ग पर बड़े हादसे का इन्तज़ार : लाचार उपायुक्त — 8

वर्ष 28 अंक 13 फरीदाबाद, शुक्रवार, 1-15 मई 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

किसानों से चौधरी छोटू राम

चमन जारे- सियासत में खामोशी मौत है बुलबुल यहां की ज़िंदगी पाबंदि-ए-रस्मे फुग़ां तक है
(ए बुलबुल राजनीति के बाग़ में चुप रहना मृत्यु को बुलावा देना है। राजनीति की दुनिया में ज़िंदा रहना है तो तू अपनी मांगों के लिये शोर मचा, हुंकार भर)-

देरी से दुर्घटना भली : केजरीवाल की हवा निकली

आप के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अखिल भारतीय राजनीतिक हस्ती बनने की महत्वाकांक्षा 22 अप्रैल की जंतर-मंतर पर किसान रैली में गजेन्द्र सिंह राठौर की पेड़ से लटक कर नाटकीय घटनाक्रम में हुई आकस्मिक मौत से धराशाही हो गयी। योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण जैसे दर्जनों पार्टी-स्तंभ जिस तरह सार्वजनिक रूप से लात मार कर बाहर किये गये थे, उससे केजरीवाल के दिल्ली दरबार ने न सिर्फ़ पार्टी काडर में अपनी साख खो दी थी बल्कि सारे देश में शुभचिन्तकों की भारी संख्या को भी निराश किया था। जहां दिल्ली पर कब्जे के बाद पार्टी को अखिल भारतीय स्वरूप पाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से आगे बढने में यादव-भूषण खेमा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था, 67 विधायक जेब में आते ही केजरीवाल ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली।

मज़दूर मोर्चा, दिल्ली ब्यूरो

भ्रष्टाचार की राजनीति ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। किसान की राजनीति करके वे अखिल भारतीय नेता बनना चाहते थे। इस क्रम में उन्होंने और उनके लग्गुओं-भग्गुओं ने सावधानी बरतने के जाने-पहचाने मुहावरे 'दुर्घटना से देरी भली' को उलट कर 'देरी से दुर्घटना भली' बना दिया। स्वयं को किसान हितैषी सिरमौर स्थापित करने की ऐसी पड़ी थी कि 22 अप्रैल की किसान रैली में सामने किसान फ़ांसी पर लटकता रहा और कुमार विश्वास, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे वरिष्ठतम 'आप' नेताओं की मंच से लतरानियां चलती रहीं। यहां तक कि सभास्थल से गजेन्द्र का शव पेड़ से गिरने और अस्पताल ले जाय जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल निर्विकार भाव से खुद को देश के किसान की असली आशा सिद्ध करते रहे।

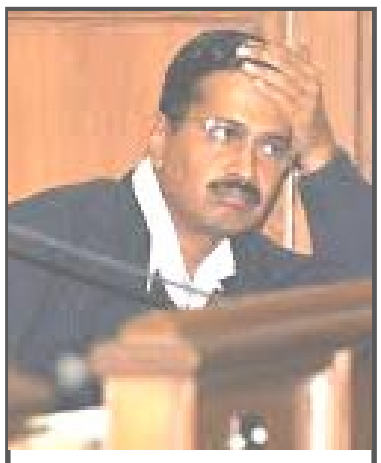

हाय, यह क्या हुआ

घटनास्थल के वीडियो फुटेज और बाद के विवरणों से स्पष्ट है कि मृतक गजेन्द्र का इरादा आत्महत्या करने का नहीं था। उसे नाटकीय रूप से किसानों के शोषण को प्रस्तुत करने के लिये इस्तेमाल किया गया। गजेन्द्र स्वयं भी मीडिया में आना चाहता रहा होगा। तभी उसने फ़ोन से घर वालों व मित्रों को सूचना दी थी कि वह टीवी के पर्दे पर दिखाया जा रहा है। यह भी जाहिर है कि उसे पेड़ पर चढाने, उसके हाथ में 'आप' का चुनाव चिन्ह झाड़ू पकड़ाने और उसकी नाटकीयता का उत्साहवर्धन करने का काम पेड़ के नीचे खड़े पार्टी के वालेंटियर कर रहे थे। इस दौरान मंच पर बैठे पार्टी के तमाम नेतागण के हाव-भाव से भी नहीं लगता था कि उन्हें गजेन्द्र द्वारा आत्महत्या किये जाने की आशंका रही होगी।

ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने (धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता) के अंतर्गत दर्ज किया गया केस अन्ततःसदोष मानव-वध (धारा 304 भरतीय दण्ड संहिता) में बदल दिया जाय तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके लिये सिद्ध यह करना होगा कि जानबूझ कर गजेन्द्र को ऐसी नाटकीयता के लिये तैयार किया गया था जिसमें जान जाने का खतरा था। यदि किसी को पेड़ पर चढकर फ़ांसी का फंदा बनाने और उसमें अपनी गर्दन डाल कर लटकने का अभिनय करते हुए राजनीतिक नारे लगाने के लिये साधा गया हो और अचानक पांव फ़िसलने से वह अनचाही मृत्यु का शिकार हो जाय तो क़ानून यही निष्कर्ष निकालेगा कि उसकी मौत की जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने उसे इस परिस्थिति में पहुंचाया था। करने वाले के लिये यह दुर्घटना हो सकती है पर करवाने वालों को सदोष मानव वध का दोष भुगतना पड़ेगा।

क्या दाल में कुछ काला है? गजेन्द्र के परिजनों के मुताबिक वह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और पार्टी में नम्बर दो मनीष सिसोदिया के सम्पर्क में था। उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षायें भी जाहिर हो चुकी हैं। जबकि केजरीवाल समेत 'आप' के तमाम बड़े नेताओं ने इस प्रकरण पर माफ़ी से लेकर आंसू बहाने और मुआवज़ा घोषित करने की तत्परता दिखाई है, सिसोदिया ने चुप्पी साधे रखी। जिस पत्र को मृतक गजेन्द्र के हाथ से निकला सुसाइड नोट बताया जा रहा था वह किसी और की ही लिखावट में होने का दावा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मृतक और सिसोदिया के बीच कॉलडिटेल भी निकलवा रही है ताकि उनकी परस्पर घनिष्ठता को भी जांचा जा सके। गजेन्द्र की उस दिन की गतिविधियों व मेल-मुलाकातों की छानबीन से भी उसके इरादों/तैयारियों पर रोशनी पड़ेगी। लब्बोलुआब यह कि स्वयं को सबसे बड़ा किसान हितैषी सिद्ध करने के लिये आयोजित रैली का 'आप' के लिये परिणाम यह हुआ कि उसे सीधे किसान हत्यारा होने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। विडंबना यह कि कुछ ही दिनों पहले फ़सल तबाही के मामले में बीस हज़ार रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा घोषित कर केजरीवाल ने वास्तव में अन्य पार्टियों के मुकाबले स्वयं को 'किसान हितैषी' की दौड़ में सबसे आगे कर लिया था। दरअसल यहां भी जेब में 67 विधायक होने का अभिमान उन्हें ले डूबा। अन्यथा किसान रैली की कोई जरूरत ही नहीं थी। बस उन्हें मुआवजे के चेक समारोह कर किसानों में बांटने थे। वे किसान-हीरो बनने की राह पर होते। पर यह सन्तुलन 37 सीटें आने पर होना था, जिसे 67 सीटों ने बिगाड़ कर रख दिया।

इस मौत की आड़ में किसान पर हो रही सारी राजनीति वोटों के नज़रिये से हो रही है, न कि किसान के। गजेन्द्र की मौत का नतीज़ा कुछ भी निकले, किसान की जिन्दगी पहले की तरह दुश्वार रहेगी।

मीडियाबाजी चलती रही....

किसान गजेन्द्र ने पेड़ पर काफ़ी वक्त गुजारा। इस बीच वह नारे भी लगाता रहा और अपने गमछे से आत्महत्या की तैयारी को नाटकीय अन्दाज़ भी देता रहा। इस दौरान मीडिया के कैमरे उसकी गतिविधियों को लाइव फ़ीड के रूप में दिखाते रहे। जब वह फ़िसल कर लटक लिया तब भी मीडिया के कैमरे यूं ही तने रहे। बाद में स्टूडियो में हर चैनल के एंकर को उत्तेजना भरी आवाज़ में पुलिसकर्मियों व राजनीतिक प्राणियों को इस अकाल मौत के लिये जवाबदेह ठहराने में एक से बढ कर एक रूपों में देखा जा सकता था। दो दिन बाद 'आज तक' की एंकर अंजना ओम कश्यप ने तो कमाल ही कर दिया । वह मृतक की 13 वर्षीय बेटी को कैमरे पर लाइव ले आई और उसके मुकाबले 'आप' के आशुतोष को खड़ा कर दिया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा यहीं तक नहीं थी। इस शो के लिये अंजना ओम कश्यप ने विशेष रूप से मेकअप और गेटअप कर रखा था। वह कुछ अलग ही चमक रही थी। क्यों न हो, उसे भी पता था कि कार्यक्रम में गजेन्द्र की बेटी के आने से टी आर पी आसमान जो छूने लगेगी।

ख़बर दार

हरियाणा स्कूलों में गीता अनिवार्य

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की घोषणा

हरियाणा की भाजपाई सरकार ने स्कूलों में गीता का पढना-पढाना अनिवार्य कर दिया है। तर्क यह है कि इससे बच्चों की मानसिक प्रगति होगी। वे सदाचारी होने के साथ-साथ पढाई में ज़्यादा रूचि लेंगे। गीता के कर्मयोग में ही समाज की उन्नति छिपी है। सोये हुए खट्टर से 'मज़दूर मोर्चा' ने एक काल्पनिक साक्षात्कार किया।

म.मो.-क्या वाकई गीता के कर्मसिद्धान्त के अनुसार ही संसार चल रहा है?

खट्टर-बिल्कुल-ऐसा ही है, आखिर मुझे भी तो इसी कर्म सिद्धांत ने राज्य का मुख्यमंत्री बनवाया है। वरना न मैंने पहले राज्य के लिये कुछ किया था और न अब कर रहा हूं। बस कर्मों के फ़ल की ही तो खा रहा हूं।

म.मो. लोग यह समझना चाहते हैं कि आपकी सरकार कुछ करती हुई क्यों नहीं नज़र आती?

खट्टर-कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जब हमें बैठे-बिठाये सत्ता मिल गयी है। हमारे पूर्व कर्मों का फ़ल तो हमें मिलना ही है, फ़िर काम करके क्यों क्लेश बढायें?

म.मो.-इस बार किसानों की सारी फ़सल तबाह हो गयी और आपकी सरकार उन्हें 200-300 के चेक पकड़ा रही है। यहां तक कि किसान आत्महत्यायें भी कर रहे हैं। उन्हें किन कर्मों का फल मिल रहा है?

खट्टर-अरे मैं 200-300 का चेक तो दे रहा हूं। हुड्डा तो दो-दो तीन-तीन रुपये के चेक दिया करता था। रही बात किसान के कर्म की तो उन्होंने ही तो मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देने का कर्म किया था। अब फ़ल से शिकायत कैसी?

म.मो-उत्तराखंड और नेपाल वालों ने क्या कर्म किया जो वहां जल-प्रलय/भूकम्प आये?

खट्टर-उत्तराखंड के लोगों का कर्म जो मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई और अब राहुल गांधी से केदारनाथ के कपाट खुलवाये।

मनोहर लाल खट्टर : मौज तो अब आई है

म.मो.-बेचारे केजरीवाल ने कौनसा कर्म किया था जो एक किसान हत्या उसके गले पड़ गयी?

खट्टर-एक तो उसने अमितशाह की रणनीतिक पसंद किरण बेदी को चुनाव में हराया। इस कर्म का फ़ल तो उसे भुगतना ही था। दूसरे, वह 67 विधायक जिता कर लाया और भाजपा के खाते में सिर्फ़ 3 सीटें छोड़ी। उसका यह कर्म मोदी जी को भी नहीं भाया, गीता के भगवान को क्योंकर भाता?

म.मो.-अशोक खेमका को आपने किस कर्म की सज़ा दी?

खट्टर-यह खेमका को सज़ा नहीं बल्कि रामबिलास शर्मा को उनके कर्मों का पुरस्कार मिला है।

भू-अधिग्रहण मोदी का वाटरलू

इस वर्ष के अन्त में बिहार विधान सभा के चुनाव क्या मोदी का वाटरलू सिद्ध होंगे? देश के तमाम देहातों में एक ही डर छाया हुआ है कि मोदी किसानों की ज़मीन हड़प लेगा। जानकारों का मानना है कि बस मोदी को अपने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर डटे रहने की जरूरत है और बिहार चुनाव में उसकी भाजपा का सूपड़ा साफ़ होगा ही होगा।

यह कोई रॉकेट साईस भी नहीं है। बिहार में चुनाव ग्रामीण वोटरों के दम पर ही जीते जाते हैं। एक ओर मोदी के भूमि बिल का हव्वा और दूसरी ओर कुदरत की मार से फ़सल तबाही। इन सबके बीच जुम्लेबाज़ी में सिद्धहस्त मोदी सरकार की खोखली राहत घोषणायें। किसान को न मंडी में समर्थित मूल्य मिल रहा है और न बढते कर्ज से मुक्ति के आसार उसे नज़र आ रहे हैं। मोदी की जंग लगी सरकारी मशीनरी किसानों तक घोषित मुआवज़ा भी नहीं पहुंचा पा रही है।

ध्यान रहे कि कुछ ही माह पहले मोदी ने स्वयं को नसीब वाला कहा था। उनका दावा था कि अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम उनके नसीब से ही गिरे हैं, जिससे आम उपभोक्ता को अगर अच्छे दिन नहीं तो इतने बुरे दिन भी नहीं देखने पड़े हैं। पर यह फ़ोकट का नसीब कब तक साथ देता? बेवक्त बरसात ने रबी की फ़सलें चौपट कर दी और किसान को मोदी की ढोल में पोल नज़र आने लगा है?

मनमोहन सिंह के मुकाबले मोदी तेज़ी से 'काम' करने वाले सिद्ध हुए हैं। मनमोहन सिंह को जिस जनविरोधी मुकाम पर पहुंचने में 8 वर्ष लगे, मोदी ने वह मुकाम 8 माह में ही पा लिया। तब जनता ने एक के बाद एक चुनावों में कांग्रेस को अस्वीकृत करने का सिलसिला चलाया था। इसी तर्ज पर मोदी और भाजपा का सिलसिला भी बनता नज़र आ रहा है। दिल्ली में शुरूआत हो चुकी है और अब अगला पड़ाव बिहार नज़र आता है।

बस मोदी को इतना ही करना है कि वह अपने भू-अधिग्रहण अध्यादेश पर अड़ा रहे। बाकी काम बिहार के किसान कर देंगे।